<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>रिट याचिका संख्या 99/ 2019 (एस/बी)</u>

साथ में

स्टे आवेदन संख्या 3074/ 2019

डॉ. परवीन ....

याचिकाकर्ता

बनाम

महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और अन्य

.........प्रत्यर्थी(गण)

श्री ज्ञानंत कुमार सिंह और सुश्री जॉयस इरविन।श्री बी.डी.उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विकास पांडे द्वारा सहायता प्राप्त, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता थे।

<u>फैसला सुरक्षितः11.03.2019</u>

<u>निर्णय दिया गयाः19.03.2019</u>

<u>संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूचीः</u>

1. (1993) 4 एससीसी 357
2. ए. आई. आर 1991 एस. सी. 532
3. (2004) 11 एससीसी 402
4. ए. आई. आर 1995 एस. सी. 1056
5. ए. आई. आर. 1993 एससी 763
6. (1994) 5 जे. टी. (एससी) 299
7. ए. आई. आर 2003 एस. सी. 1344
8. 2003 (2) कार्लजे 26
9. ए. आई. आर 1964 एस. सी. 477
10. (2008) 14 एससीसी 171
11. ए. आई. आर 1961 एस. सी. 970
12. (1952) 1 KB 338
13. ए. आई. आर 1958 एससी 398
14. ए. आई. आर 1965 एससी 111
15. (1972) 4 एससीसी 257
16. ए. आई. आर 1955 एस. सी. 233
17. ए. आई. आर 1953 बोम 133
18. (2010) 13 एससीसी 336
19. (2004) 12 एस. सी. सी. 299
20. (2005) 7 एससीसी 227

21. (2004) 4 एससीसी 245
22. (2001) 8 एससीसी 574
23. (1989) 2 एस. सी. सी. 602
24. (2003) 4 एससीसी 104
25. (1995) 2 एस. सी. सी. 532
26. (1995) पूरक 4 एस. सी. सी. 169
27. (2004) 3 एससीसी 172
28. (1993) 1 एससीसी 148
29. (2009) 3 एससीसी 124
30. ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1283
31. (2009) 11 एससीसी 678
32. (2004) 7 एससीसी 405
33. (2001) 5 एससीसी 508
34. (1995) 6 एससीसी 749
35. (1986) 1 एससीसी 133
36. (2000) 5 एससीसी 630
37. (1974) 4 एससीसी 3
38. ए. आई. आर 1977 एससी 448
39. (2005) 7 एससीसी 764
40. (2007) 8 एस. सी. सी. 418
41. (2008) 12 एससीसी 292
42. (2002) 4 एससीसी 160
43. (2010) 4 एससीसी 192
44. (1978) 4 एससीसी 336
45. (1966) I LLJ 458 SC
46. ए. आई. आर 1991 एस. सी. 1260
47. (1995) 1 एस. सी. सी. 745

कोरमः- **<u>माननीय रमेश रंगनाथन, सी.जे.</u>**
<u>माननीय एन.एस. धनिक, जे।</u>
<u>रमेश रंगनाथन, सी.जे.</u>

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, जिसमें नैनीताल में बैठे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, सर्किट द्वारा पारित OA No616/2018 दिनांक 19.02.2019 में आदेश सरशियोरेराई करने के लिए प्रमाणपत्र की रिट की मांग की गई है; 14.05.2018 दिनांकित स्थानांतरण आदेश सरशियोरेराई करने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट, और 14.05.2018, 18.05.2018 और 08.10.2018 पर पारित आदेशों को राहत देने के लिए; और हस्तांतरण के विवादित आदेश और न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए।

2. तथ्य, सीमित सीमा तक आवश्यक, यह है कि याचिकाकर्ता को अब तक 21.08.2015 की कार्यवाही द्वारा जोरहाट, असम में स्थानांतरित किया गया था।स्थानांतरण का यह आदेश लंबित यौन उत्पीड़न की

शिकायत की पृष्ठभूमि में प्रभावी हुआ था, और फर्जी पीएचडी प्रदान करने के संबंध में जांच की मांग करते हुए उनके और उनके पति द्वारा विभिन्न अधिकारियों को दायर किए गए कई अभ्यावेदन थे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (संक्षेप में "आईसीएफआरई") में आईएफएस अधिकारियों के एक गुट को डिग्रियां, साहित्यिक चोरी आदि।अपने स्थानांतरण को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए, याचिकाकर्ता ने 2015 का OA नंबर 4081 दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच, नैनीताल सर्किट बेंच (संक्षेप में "कैट") का दरवाजा खटखटाया।

3. ओ.ए. में एक विस्तृत आदेश द्वारा संख्या 4081/2015 दिनांक 13.07.2016 को कैट ने स्थानांतरण के विवादित आदेशों को दुर्भावना से प्रेरित मानते हुए रद्द कर दिया।कैट ने पाया कि स्थानांतरण का उद्देश्य आवेदक को दंडित करना और हटाना था, जो उत्तरदाताओं के लिए असुविधाजनक हो गया था; याचिकाकर्ता, एक महिला, ने फर्जी पीएचडी से संबंधित मुद्दों को उठाने में साहस के साथ काम किया था। संस्थान में प्रचलित डिग्रियाँ और बड़े पैमाने पर साहित्यिक चोरी; उनका स्थानांतरण उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का परिणाम था; यह अधिकारियों का काम था कि वे इन आरोपों की जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन करें, और अपना घर व्यवस्थित करें; हालाँकि स्थानांतरण के आदेश से उसकी रैंक कम नहीं हुई या उसका वेतन कम नहीं हुआ, लेकिन इससे उसे बहुत असुविधा होने की संभावना थी क्योंकि उसने हाल ही में एक बच्चे को गोद लिया था जिसे परिचित परिवेश से हटा दिया जाएगा; यौन उत्पीड़न, फर्जी पीएचडी जैसे मुद्दे उठाने के लिए उन्हें किसी भी सूरत में दंडित नहीं किया जा सकता। डिग्री और साहित्यिक चोरी; आवेदक एक मुखबिर था; और यद्यपि उसने इस पर कोई दावा नहीं किया था, इतने शब्दों में, वह व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2011 और व्हिसल ब्लोअर्स से संबंधित कई निर्णयों के तहत सुरक्षा की हकदार थी।

4. स्थानांतरण के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया, याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को छुट्टी नियमों के प्रावधानों के अनुसार कुछ छुट्टी के विरुद्ध समायोजित करने का निर्देश दिया गया; पहले प्रतिवादी को संस्थान के कामकाज की समीक्षा करने और आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए एक उच्च शक्ति समिति गठित करने पर विचार करने के लिए कहा गया था; और, यदि आरोप निराधार पाए गए, तो यह उत्तरदाताओं पर निर्भर है कि वे आवेदक के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

5. इससे व्यथित होकर, आईसीएफआरई ने 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 6736 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैट, नैनीताल सर्किट पीठ के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए 02.08.2016 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया।इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने 2016 की विशेष अनुमति (सी) संख्या 26267 दिनांक 14.09.2016 में अपने आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। रिट याचिका (सी) क्रमांक 6736 ऑफ़ 2016 दिनांक 02.08.2016 में। इसके बाद आदेशानुसार आई.ए. सिविल अपील संख्या 9179 / 2016 दिनांक 24.10.2016 में नंबर 2-3, सुप्रीम कोर्ट ने अपील और लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए कहा कि 14.09.2016 को पहले पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय से 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 6736 पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इसका व्यवसाय अनुमति देगा। तदनुसार, सिविल अपील और सभी अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

6. संस्थान द्वारा अपने वकील को दिनांक 12.04.2018 को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि वे रिट याचिका को वापस लेने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और इसके बाद, मांगों के अधीन याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार करेंगे। प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण, और यह निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.2016 के पैराग्राफ 35 में उल्लिखित किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना लिया जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए, इसका निपटारा कर दिया, रिट याचिका को लंबित आवेदनों के साथ नहीं दबाया गया, और संस्थान को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसके लिए उक्त आदेश के पहले पैराग्राफ के संदर्भ में, प्रशासनिक आवश्यकताओं की मांगों के अधीन, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार करना था।

7. इसके बाद, हस्तांतरण का विवादित आदेश 14.05.2018 पर पारित किया गया।उक्त आदेश में लिखा गया है कि आई. सी. एफ. आर. ई. के महानिदेशक ने प्रशासनिक कारणों से संस्थान में 18 वैज्ञानिकों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।याचिकाकर्ता का नाम उक्त सूची में एस. एल. संख्या में परिलक्षित हुआ था।कार्यवाही में अग्रेतर कहा गया है कि सभी वैज्ञानिकों को तुरंत अपनी नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था; संस्थानों के संबंधित निदेशक आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेंगे; और ऐसे वैज्ञानिकों के आरोप त्याग/धारणा रिपोर्ट, नियत समय पर भेजी जानी चाहिए।

8. यह आरोप लगाते हुए कि दिनांक 14.05.2018 का यह स्थानांतरण आदेश भी दुर्भावना से प्रेरित था, याचिकाकर्ता ने OA संख्या 330/616/2018 दायर करके फिर से कैट, सर्किट बेंच नैनीताल का दरवाजा खटखटाया। अपने आदेश दिनांक 19.02.2019 (इस रिट याचिका में लागू आदेश) में, न्यायाधिकरण ने कहा कि विवाद में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सुधार के लिए आवेदन दाखिल करने के परिणामस्वरूप उस पर लगाई गई सजा के रूप में था। आईसीएफआरई में कुप्रशासन और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की उनकी शिकायत; और क्या यह दुर्भावना से दूषित था या प्रशासन की सेवा और हित की अनिवार्यताओं के तहत था।

9. इसके बाद, न्यायाधिकरण ने पाया कि तबादलों और पोस्टिंग पर निर्णय पर सवाल उठाना या उन अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन करना, जिन्हें पोस्ट किया जा सकता था या विचार किया जा सकता था, यह उसका कार्य नहीं था, या उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं था, क्योंकि ये मामले विशेष रूप से संबंधित प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि स्थानांतरण और पोस्टिंग सेवा की घटना थी, और जब तक कि यह दुर्भावना से या पूरी तरह से असंगत विचारों से दूषित न हो, या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो, न्यायाधिकरण स्थानांतरण या पोस्टिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।न्यायाधिकरण ने **एस.एल. में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों अब्बास[1]; शिल्पी बोस[2]; गोबरधन लाल[3]; एस.एस. कौरव और अन्य तथा एम. शंकरनारायणन, आईएएस[5]** का हवाला दिया और उसके बाद देखा गया कि, स्थानांतरण के मुद्दे पर निर्णयों के आलोक में, निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

1) स्थानांतरण सेवा की एक शर्त है।

2) यह कर्मचारी की स्थिति या परिलब्धि या वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

3) कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर पोस्टिंग पाने या किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय के लिए सेवा करने का चयन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

4) यह निर्धारित करना नियोक्ता के विशेष अधिकार क्षेत्र में है कि किस स्थान पर और कितने समय तक किसी विशेष कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता है।

5) स्थानांतरण आदेश जनहित या प्रशासनिक आवश्यकता में पारित किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से या अनावश्यक विचार के लिए या कर्मचारी को प्रताड़ित करने के लिए और न ही इसे राजनीतिक दबाव में पारित किया जाना चाहिए।

6) स्थानांतरण आदेश के खिलाफ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक समीक्षा की बहुत कम गुंजाइश है और यह केवल तभी प्रतिबंधित है जब स्थानांतरण आदेश वैधानिक नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है या दुर्भावनापूर्ण साबित होता है।

7) दुर्भावना के मामले में, कर्मचारी को विशिष्ट दावे करने होंगे और त्रुटिहीन साक्ष्य जोड़कर उसे साबित करना होगा।

8) जिस व्यक्ति के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, उसे नाम से एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

9) राज्य या नियोक्ता द्वारा जारी स्थानांतरण नीति या दिशानिर्देशों में कोई वैधानिक बल नहीं है क्योंकि यह मात्र विभागीय कर्मियों की समझ के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

10) न्यायालय के पास स्थानांतरण आदेश को केवल इस आधार पर रद्द करने की शक्ति नहीं है कि इससे कर्मचारी, उसके परिवार के सदस्यों और बच्चों को व्यक्तिगत असुविधा होगी, क्योंकि इन विचारों पर विचार करना नियोक्ता के विशेष क्षेत्र में आता है।

11) यदि स्थानांतरण काआदेश कर्मचारी के बच्चों के शैक्षणिक सत्र के मध्य में किया जाता है तो न्यायालय/न्यायाधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता।इस तरह की व्यक्तिगत शिकायत पर विचार करना नियोक्ता का काम है।

10. इसके बाद, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए नई गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही उसका स्थानांतरण कर दिया गया था, और उनके जोधपुर स्थानांतरण के कारण उन्हें जांच कार्यवाही में भाग लेने के लिए देहरादून आना होगा, जिसमें समय और धन शामिल होगा।इस तर्क पर, न्यायाधिकरण ने माना कि, जांच में भाग लेने के दौरान, याचिकाकर्ता आधिकारिक ड्यूटी पर होगी, और जांच में भाग लेने के दौरान उसके द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति पाने की हकदार होगी।

11. स्थानांतरण समिति की संरचना को याचिकाकर्ता की चुनौती पर, जिसमें अन्य लोगों के अलावा, श्री ए.एस. रावत, ट्रांसफ़र समिति के प्रमुख हैं भी शामिल थे, जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी, और जिनके खिलाफ जांच लंबित थी, और श्री रमन नौटियाल, "विशेष आमंत्रित सदस्य" के रूप में, जिनके खिलाफ उनके पति ने अदालत में याचिकाएं दायर की थीं, जो लंबित हैं। न्यायाधिकरण ने माना कि प्रत्यर्थीओं ने समिति के सदस्यों की ओर से प्रतिशोध से इनकार किया था; श्री ए.एस. का समावेश स्थानांतरण समिति में रावत और श्री रमन नौटियाल का कोई विशेष महत्व नहीं था; वास्तव में, स्थानांतरण समिति के अन्य सदस्य भी थे जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया था; यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानांतरण समिति ने केवल श्री रावत एवं श्री नौटियाल के निर्देश पर ही कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय लिया; आवेदक के स्वयं दिखाने पर, उसे उक्त दो व्यक्तियों को हटाने के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार था,

जिसे उसने नहीं करने का फैसला किया; और यह एक और कारक था जो उसके दुर्भावना और प्रतिशोध के तर्क का समर्थन नहीं करता था ।

12. याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि वह लंबे समय से एक परियोजना पर काम कर रही थी जो उसके स्थानांतरण के कारण अधूरा रह जाएगा, और प्रतिवादी के इस तर्क पर कि, वर्तमान में, वह किसी भी परियोजना में शामिल नहीं थी, न्यायाधिकरण ने कहा कि, चल रही परियोजना की स्थिति चाहे जो भी हो और इसे याचिकाकर्ता द्वारा संभाला जा रहा था या नहीं, यह सुनिश्चित करना विभाग/संगठन के प्रमुख का एकमात्र विशेषाधिकार था कि संगठन का दैनिक कामकाज जारी रहे। न्यायाधिकरण के पास महानिदेशक को यह निर्देश देने की विशेषज्ञता नहीं थी कि संगठन के कामकाज और प्रबंधन को सर्वोत्तम तरीके से कैसे संचालित किया जाए; और न्यायाधिकरण के आदेश पर संगठन के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।न्यायाधिकरण ने **एन.के. सिंह**[6] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस संबंध में ।

13. याचिकाकर्ता की उस जल्दबाजी की शिकायत पर जिसमें उसके स्थानांतरण आदेश को लागू करने की मांग की गई थी, न्यायाधिकरण ने माना कि ये एक अधिकारी को कार्यमुक्त करने के लिए प्रदान की गई औपचारिकताएं थीं, और यह प्रशासन को देखना था कि औपचारिकताओं का सबसे अच्छा पालन कैसे किया जाए; प्रशासन का कोई भी कार्य, यदि गैरकानूनी या अनियमित हो, तो आवेदक को प्रशासनिक निर्देशों के तहत उपलब्ध अधिकारों में कोई नुकसान नहीं होगा और न ही होगा; और गलत-प्रशासनिक कार्य या चूक, यदि कोई हो, किसी भी तरह से आवेदक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।

14. याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि आज भी वही परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जिनके आधार पर उसका पहले स्थानांतरण किया गया था, न्यायाधिकरण ने माना कि, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से, यह स्पष्ट था कि पिछले स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था। स्थानांतरण का उद्देश्य याचिकाकर्ता को दंडित करना और हटाना था, जो उत्तरदाताओं के लिए असुविधाजनक हो गया था और सार्वजनिक हित में नहीं था।न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रत्यर्थीओं ने तर्क दिया था कि संगठन में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच के लिए कार्रवाई की गई थी; वर्तमान स्थानांतरण न तो दंडात्मक था और न ही दुर्भावनापूर्ण था, और प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर किया गया था, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना जिसका उल्लेख पिछले ओ.ए. में न्यायाधिकरण के आदेश में किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्थानांतरण को चुनौती देते हुए दायर किया गया; उन्हें अलग नहीं किया गया था, बल्कि कई अन्य अधिकारियों के साथ उनका तबादला कर दिया गया था; पिछले स्थानांतरण के आसपास की वही परिस्थितियाँ आज की तारीख में मौजूद नहीं थीं; वर्तमान स्थानांतरण ने आवेदक की स्थिति या परिलब्धियों या वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है; यह प्रशासक को निर्धारित करना था कि किस स्थान पर और कितने समय के लिए किसी विशेष कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता है; यह तथ्य कि अन्य अधिकारियों का लंबे समय से स्थानांतरण नहीं किया गया था, स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता; कर्मचारी दुर्भावना के आधार पर स्थानांतरण के आदेश पर केवल विशिष्ट दावे करके और त्रुटिहीन साक्ष्य जोड़कर उसे साबित कर सकता है, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने में असमर्थ था; और जबकि कई व्यक्तियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए थे, उन सभी को नाम से प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

15. न्यायाधिकरण ने **फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन**[7] को संदर्भित किया, जिसमें यह कहा गया था कि दुर्भावना के बारे में आरोप अस्पष्ट रूप से नहीं लगाए जा सकते हैं और यह विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए।न्यायाधिकरण ने **श्रीमती बी. नागरत्नम्मा और एक अन्य**[8], के मामले में दिए गए फैसले पर भी ध्यान दें। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबंधित अधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल. पी. सी.) का तब तक हकदार नहीं था जब तक कि नियमों के से आवश्यकता के अनुसार प्रभार नहीं सौंपा जाता।इसके बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि ये प्रशासनिक कार्य स्थानांतरण आदेश के अनुसार शुरू किए गए थे और इसलिए कहा जा सकता है कि उक्त कृत्यों से आवेदक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

16. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों और स्थानांतरण पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के आलोक में, यह संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण और नियुक्ति प्रशासनिक कारणों से थी, और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कारणों से था, और दुर्भावना या सजा के माध्यम से नहीं किया गया था।ओ.ए. तदनुसार, बर्खास्त कर दिया गया था।इससे व्यथित, वर्तमान रिट याचिका।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ज्ञानंत कुमार सिंह ने कहा कि न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आदेश महिलाओं के यौन उत्पीड़न की धारा 12 (1) और (3) का उल्लंघन था। कार्यस्थल पर (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (इसके बाद इसे "2013 अधिनियम" कहा जाएगा); दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत वचनपत्र, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका (सी) संख्या 6736/2016 दिनांक 12.04.2018 को आदेश पारित किया गया था, को स्थानांतरण समिति के समक्ष नहीं रखा गया था; इस उपक्रम के लिए प्रतिवादी-संस्थान को कैट के पहले के फैसले के पैराग्राफ 35 पर ध्यान देने की आवश्यकता थी; ऐसा तभी होता जब दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश स्थानांतरण समिति के समक्ष रखा गया होता, क्या वह इस पर विचार कर सकती थी कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण न्यायाधिकरण ने अपने पहले के आदेश के पैराग्राफ 35 में जो देखा था उसके विपरीत था या नहीं; उसे कोई काम न देने में प्रतिवादी-संस्थान का आचरण, और स्थानांतरण के पहले आदेश के बाद और स्थानांतरण के बाद के आदेश से पहले उनके कृत्यों से पता चलता है कि स्थानांतरण के बाद के आदेश को दुर्भावना से प्रभावित किया गया था; याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक कोई भी काम नहीं दिया गया और उसका वेतन भी नहीं दिया गया; स्थानांतरण समिति में दो सदस्य शामिल थे जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता और उसके पति ने गंभीर आरोप लगाए थे; याचिकाकर्ता का स्थानांतरण, न्यायाधिकरण के समक्ष दिए गए आदेश द्वारा, उस अवधि के दौरान पारित किया गया था जब उसकी यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच अभी भी लंबित थी; स्थानांतरण का आदेश पारित होने के बाद ही उक्त जांच बंद की गई थी; जांच समिति के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ता ने कैट, सर्किट बेंच नैनीताल का दरवाजा खटखटाया, जिसके समक्ष मामला अभी भी लंबित है; संस्थान के पूर्व सचिव श्री वी. खांडेकर द्वारा प्रस्तुत नोट में अधिकारियों के विचारों को दर्ज किया गया है कि देहरादून में उनकी निरंतर उपस्थिति से माहौल और खराब हो जाएगा, और वह दूसरों को फंसाने के प्रयासों में शामिल हो सकती हैं; और इन कारकों को देखते हुए, उसे देहरादून से दूर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है; न्यायाधिकरण ने यह मानने में गलती की थी कि याचिकाकर्ता स्थानांतरण समिति में दो सदस्यों को शामिल करने के बारे में शिकायत कर सकता था, और उन्हें बाहर करने की मांग करनी चाहिए थी। स्थानांतरण समिति द्वारा कई कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय लेने के बाद ही याचिकाकर्ता को पता चला कि

ये दोनों सदस्य भी स्थानांतरण समिति का हिस्सा थे; याचिकाकर्ता, ऐसी परिस्थितियों में, स्थानांतरण समिति के गठन के संबंध में अधिकारियों से शिकायत नहीं कर सकता था; याचिकाकर्ता को यह सूचित किए जाने पर कि वह दो स्टेशनों के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकती है, अधिकारियों से यह खुलासा करने के लिए कहा कि कौन से उम्मीदवार स्थानांतरण के लिए पात्र हैं; चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण पर इस आधार पर सवाल उठाया था कि यह दुर्भावना से दूषित था, इसलिए उसके लिए न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दावा याचिका में, या दो अन्य स्टेशनों में से किसी एक पर तैनात होने के विकल्प को इंगित करना पूरी तरह से अनावश्यक था। इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका; जबकि कहा जाता है कि जिन वैज्ञानिकों ने 10 साल से अधिक सेवा की थी, उन्हें स्थानांतरण के लिए पहचाना गया था, वहीं कई अन्य वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने देहरादून में याचिकाकर्ता की तुलना में कहीं अधिक वर्षों की सेवा दी थी, और फिर भी उनके मामले स्थानांतरण समिति के समक्ष नहीं रखे गए थे। , स्थानांतरण के लिए बहुत कम विचार किया जा रहा है; यह तथ्य कि पहला कार्यमुक्ति आदेश जल्दबाजी में जारी किया गया था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि 14.05.2018 को स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने के आधे घंटे के भीतर ही कार्यमुक्ति आदेश जारी कर दिए गए थे; इसके चार दिन बाद 18.05.2018 को एक और राहत आदेश दिया गया, और उसके कुछ महीने बाद 08.10.2018 को एक और राहत आदेश दिया गया; इससे याचिकाकर्ता का यह आरोप भी सही साबित होगा कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावना से प्रेरित था; उसे कोई नोटिस न देकर महानिदेशक (चौथे प्रतिवादी) के आचरण से पता चलता है कि अधिकारियों का इरादा, किसी भी तरह, उसे कार्यालय से बाहर निकालना था; दुर्भावना से संबंधित इन विशिष्ट तर्कों पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया; स्थानांतरण के आक्षेपित आदेश में स्वयं दर्ज है कि स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से था, न कि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के लिए; वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2007 के नियम 286 (3) के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक कारणों से नहीं, बल्कि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण स्थानीय व्यवस्था के विरुद्ध अपना पद छोड़कर दूसरे पद पर जाना पड़ता है; और इन आधारों पर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, साथ ही न्यायाधिकरण के समक्ष लगाए गए स्थानांतरण के आदेश को रद्द करना आवश्यक हो गया है।

18. दूसरी ओर श्री बी.डी. संस्थान की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील उपाध्याय ने कहा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने आवेदन में और इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाकर्ता दोनों में दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए थे, उन्हें प्रतिवादी ईओ-नामांकित के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ; याचिकाकर्ता 2003 से पिछले 16 वर्षों से देहरादून में काम कर रहा था; वैज्ञानिक ग्रेड-ए की सेवाएँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित की जा सकती हैं; नियम प्रत्येक स्टेशन पर केवल पाँच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करता है; उन सभी उम्मीदवारों से विकल्प आमंत्रित किए गए थे, जो स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, उनसे दो अलग-अलग स्टेशनों की अपनी पसंद बताने के लिए कहा गया था; याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सूचित किए जाने के बावजूद किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया; इसलिए, प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से बचना न्यायाधिकरण के लिए उचित था; और स्थानांतरण का आदेश संस्थान के महानिदेशक द्वारा पारित किया गया था, जिन्हें कैट के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी *ईओ-नामांकित* के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने 2018 के ओए नंबर 616 दिनांक 19.02.2019 में कैट के आदेश, दिनांक 14.05.2018 के स्थानांतरण आदेश और 14.05.2018 को पारित राहत आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की रिट की मांग की है। , 18.05.2018 और 08.10.2018.क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सर्टिओरी की रिट जारी की जा सकती है जैसे कि ऐसे मामलों में जहां आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया जाता है, या उससे अधिक है, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप या जहां, प्रदत्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है।सर्टिओरारी रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी है न कि अपीलीय।कानून की त्रुटि, जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो।सबूतों की पर्याप्तता या पर्याप्तता, और उससे निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान, सर्टिओरीरी कार्यवाही (**सैयद याकूब**[9]) में नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह अपील की अदालत के प्रांत में है।

20. यदि न्यायाधिकरण ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है, या यदि तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधार पर है, तो यह कानून की एक त्रुटि होगी जिसे सर्टिओरीरी की रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है।जहां न्यायाधिकरण द्वारा कानून का निष्कर्ष प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट गलत व्याख्या पर आधारित है, या इसकी अज्ञानता में या यहां तक कि इसकी उपेक्षा पर आधारित है या स्पष्ट रूप से उन कारणों पर आधारित है जो कानून में गलत हैं, तो उक्त निष्कर्ष हो सकता है सर्टिओरारी की रिट द्वारा सही किया गया।त्रुटि कानून की त्रुटि है या नहीं, और कानून की त्रुटि जो अभिलेख के सामने स्पष्ट है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और कानूनी प्रावधानों की प्रकृति और दायरे पर निर्भर होनी चाहिए, जिन पर गलत अर्थ लगाया गया है या उल्लंघन किया गया है। (**सैयद याकूब**[9])।

21. एक अपीलीय प्राधिकारी के विपरीत, जो रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की दोबारा सराहना कर सकता है, उच्च न्यायालय, अपने उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायाधिकरण के विचारों के स्थान पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, न ही वह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की दोबारा सराहना करेगा। न्यायाधिकरण के उस निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचना जिसके आदेश पर उसके समक्ष आपत्ति जताई गई है।यहां तक कि अगर दो विचार संभव हैं, और न्यायाधिकरण ने संभावित विचारों में से एक को लिया है, तो उच्च न्यायालय अपने उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह इस बात से संतुष्ट हो कि उसके समक्ष प्रस्तुत अन्य संभावित दृष्टिकोण सही है। अधिक आकर्षक।सबूतों की सराहना के आधार पर प्राप्त तथ्य के निष्कर्ष को रिट कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला जा सकता है या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय उस निष्कर्ष के, जो या तो विकृत है या बिना किसी सबूत के आधारित है।यदि कोई प्रावधान दो निर्माणों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, और प्राधिकरण द्वारा एक निर्माण को अपनाया गया है, तो इसका निष्कर्ष हमेशा रिट कार्यवाही में सुधार के लिए खुला नहीं हो सकता है।(**सैयद याकूब**[9])।

22. निम्नतर न्यायालय द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाणपत्र की एक उत्प्रेषण जारी की जा सकती है।इसी तरह एक रिट भी जारी की जा सकती है, जहां अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई

प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।(**सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड**[10] **सैयद याकूब** [9])।क्षेत्राधिकार के अवैध प्रयोग के मामले में प्रमाणपत्र का एक उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है, और अभिलेख के सामने स्पष्ट कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी, भले ही वे अधिकार क्षेत्र में न जाएं।यह केवल कानून की त्रुटियां हैं जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हैं, न कि तथ्य की त्रुटियां, हालांकि वे रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हो सकती हैं, जो कि कंपनी लिमिटेड[11] हो सकती हैं; नॉर्थम्बरलैंड ने सुधार किया, (**श्री अंबिका मिल्स। मुआवजा अपील न्यायाधिकरण**[1]2; **और नागेंद्र नाथ बोरा**[13]), और कानून या तथ्य की हर त्रुटि को नहीं जिसे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। (**टी. प्रेम सागर**[14]; **बचन सिंह** [15]; **नागेंद्र नाथ बोरा**[13])।

23. इसके अलावा कानून की कोई त्रुटि, जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, स्व-स्पष्ट होनी चाहिए।इसे रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए (**श्री अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड**[11]), या इसे स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परीक्षा या एक विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए (**सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड**[10]; **हरि विष्णु कामथ**[16]; **बटुक के. व्यास**[17]) यदि निर्णय सही है या नहीं, यह देखने के लिए किसी को रिकॉर्ड से परे जाना पड़े तो त्रुटि स्पष्ट नहीं कही जा सकती। यह एक ऐसी त्रुटि है जो देखने मात्र से ही सामने आ जाती है और इसके लिए उन बिंदुओं पर लंबे समय तक चलने वाली तर्क-वितर्क प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जहां संभावित रूप से दो राय हो सकती हैं।ऐसी त्रुटि के लिए अपनी ग़लती दर्शाने के लिए किसी बाहरी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी।दूसरे शब्दों में कहें तो, यह इतना स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी अदालत इसे रिकॉर्ड पर बने रहने की अनुमति न दे।(**सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड** [1]; **संत लाल गुप्ता**[18])।

24. पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क की जांच करें कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष लगाए गए स्थानांतरण के आदेश और परिणामी राहत आदेश, उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार के अभ्यास की आवश्यकता के कारण रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से पीड़ित हैंरिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2003 से एफ.आर.आई., देहरादून में काम कर रहा है। पिछले 16 वर्षों से उनके द्वारा धारण किया गया पद एक हस्तांतरणीय पद है, और नियम प्रत्येक स्टेशन पर मात्र पांच साल का कार्यकाल निर्धारित करते हैं।केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का देहरादून से जोधपुर स्थानांतरण, जैसा कि दिनांक 14.05.2018 के आदेश में ही प्रशासनिक कारणों से संदर्भित किया गया है।किसी भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी उपक्रम/संस्थान के कर्मचारी को किसी एक विशेष स्थान या अपनी पसंद के स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने का कानूनी अधिकार नहीं है।(**केंद्रीय विद्यालय संगठन**[1]; **मेजर जनरल जे.के. बंसल**[20]; **जनार्दन देबनाथ**[21]; **नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड** [22])।हस्तांतरणीय पदों के एक विशेष संवर्ग में नियुक्त एक कर्मचारी का स्थानांतरण, सेवा की एक घटना है और प्रशासनिक आवश्यकताओं में किया जाता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर तैनात होने का कानूनी अधिकार नहीं है।स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आम तौर पर सेवा की एक शर्त है और कर्मचारी के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है।लोक हित में और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए स्थानांतरण आवश्यक है।आम तौर पर, इसमें अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहां इसे प्रतिशोधात्मक तरीके से किया गया हो।जब भी किसी लोक सेवक का स्थानांतरण किया जाता है तो उसे आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन यदि स्थानांतरण पर आगे बढ़ने में कोई वास्तविक कठिनाई होती है, स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने, संशोधन

करने या रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने के लिए वह स्वतंत्र है।यदि स्थानांतरण के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी को स्थानांतरण के आदेश का पालन करना चाहिए।स्थानांतरण आदेश पर किसी भी रोक की अभ्यावेदन में, कर्मचारी के पास मात्र इस आधार पर कि उसने कोई अभ्यावेदन दिया है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसकी कठिनाई के आधार पर स्थानांतरण आदेश से बचने का कोई औचित्य नहीं है।यदि वह स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में स्थानांतरण पर आगे बढ़ने में विफल रहता है, तो वह संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उजागर करेगा।(**गुजरात विद्युत बोर्ड**[23]; **लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन** [24])।

25. प्रशासनिक आधार पर या लोक हित में लोक सेवक के स्थानांतरण में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्थानांतरण हस्तांतरण आदेश को अनुचित बनाने वाले मजबूत और बाध्यकारी आधार न हों।(**राजेंद्र च. भट्टाचार्जी** [25])।किसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए और कहाँ तैनात किया जाना चाहिए, यह प्रशासनिक प्राधिकरण को तय करना है।जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावनापूर्ण तरीके से दूषित नहीं किया जाता है या किसी परिचालन दिशानिर्देश या नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालयों को सामान्य रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (**केंद्रीय विद्यालय संगठन** [19]; **एस.एल. अब्बास**[1]; **मेजर जनरल जे.के. बंसल**[20]; **अबनि कांता राय**[26])।हस्तांतरणीय पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर तैनात रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश उसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।(**शिल्पी बोस**[2]; **मेजर जनरल जे.के. बंसल**[20])। हस्तांतरणीय पद धारण करने वाले व्यक्ति के पास, जब तक कि उसकी सेवा शर्तों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, पोस्टिंग के मामले में कोई विकल्प नहीं है।(**राजेंद्र च. भट्टाचार्जी** [25])।जब तक सेवा अनुबंध में इसके विपरीत कोई शब्द नहीं है, तब तक स्थानांतरण आदेश सेवा की एक सामान्य घटना है।(**पियरलाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड**[27])।स्थानांतरणीय पद पर, स्थानांतरण का आदेश एक सामान्य परिणाम है और व्यक्तिगत कठिनाइयाँ विभाग के विचार का विषय हैं, न कि न्यायालय के।(**राजेंद्र रॉय**[28])।जब कोई कर्मचारी अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो वह कदाचार करता है।(**नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड**[2])।स्थानांतरण आदेश का अनुपालन न करना वरिष्ठों द्वारा पारित आदेशों का पालन करने से इनकार करने के बराबर है, जिसके लिए नियोक्ता से संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है।(**पियरलाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड**[27]).

26. जब तक स्थानांतरण के आदेश को शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग या किसी वैधानिक प्रावधान (एक अधिनियम या नियम) के उल्लंघन के परिणाम के रूप में नहीं दिखाया जाता है या ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक इसे स्वाभाविक रूप से या हर प्रकार की शिकायत के लिए हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।(**गोबर्धन लाल**[3]).प्रशासन की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, नियोक्ता यह निर्णय लेने का हकदार है कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी विशेष स्थान पर किया जाना चाहिए या नहीं।नियोक्ता यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर कैसे वितरित किया जाए।प्रशासन की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, नियोक्ता यह निर्णय लेने का हकदार है कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी विशेष स्थान पर किया जाना चाहिए या नहीं।यदि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से या किसी अन्य गुप्त उद्देश्य के लिए दिया गया है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर

सकते हैं और स्थानांतरण के ऐसे आदेश को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग कानून में शक्ति का प्रयोग नहीं माना जाता है।हालाँकि, अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा दुर्भावनापूर्ण निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जाना चाहिए जब पर्याप्त और उचित सबूत हों और इस तरह के निष्कर्ष पर मनमाने ढंग से या कमजोर आधार पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। (**सिंडिकेट बैंक लिमिटेड**[30]).स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां स्थानांतरण प्रतिशोधात्मक तरीके से किया गया हो। (**पब्लिक सर्विसेज न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन** [24]; **तुषार डी. भट्ट**[31])।

27. इस सवाल पर कि क्या किए गए स्थानान्तरण सार्वजनिक हित में हैं या नहीं, आम तौर पर जांच नहीं की जाती है क्योंकि इसके लिए अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक निर्णय की आवश्यकता होगी और यह अनिवार्य रूप से संबंधित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को एक विशेष स्थान पर या अपनी पसंद के स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि एक सेवा की शर्त है, जो लोक हित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए आवश्यक है।असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अदालतें या न्यायाधिकरण, आम तौर पर, ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जैसे कि वे प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में पारित ऐसे आदेशों के संबंध में नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपीलीय प्राधिकारी थे। (**नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड** [22] **और सिया राम** [32])।

28. न्यायालय या न्यायाधिकरण प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के स्थानांतरण पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय मंच नहीं हैं। यह प्रशासन को उचित निर्णय लेना है, और ऐसे निर्णय तब तक बने रहेंगे जब तक कि वे द्वेष या बाहरी विचारों से दूषित नहीं हो जाते।(**एस.एस.कौरव**[4]). किसी न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण के आदेशों में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।(**अंजन सान्याल** [33])।स्थानांतरण के मामले में न्यायालय या न्यायाधिकरण सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों के स्थान पर अपने निर्णय नहीं ले सकते।(**गोबर्धन लाल**[3]; **कैंद्रीय विद्यालय संगठन**[19]; **जनार्दन देबनाथ**[21]; **नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन**[22]. **एस.एल. अब्बास**[1]; **बी.सी. चतुर्वेदी**[34]; **नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन**[22]; **मेजर जनरल जे.के. बंसल**[20]).

29. चूंकि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश के अवैध होने का दावा मुख्य रूप से इस आधार पर आधारित है कि यह दुर्भावना से दूषित है, इसअपास्त उन परिस्थितियों ध्यान दें देना आवश्यक है जिनके से इस आधार पर स्थानांतरण आदेश को अलग रखा जा सकता है।किसी शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण ढंग से किया जाता है यदि उसका भंडार उन लोगों के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता से प्रेरित होता है जो इसके प्रयोग से सीधे प्रभावित होते हैं। जिस शक्ति के लिए शक्ति प्रदान की गई है, उसके अलावा किसी "**विदेशी**" उद्देश्य के लिए शक्ति का उपयोग, उस शक्ति का दुर्भावनापूर्ण उपयोग है।यही स्थिति तब होती है जब कोई आदेश किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, सिवाय उस उद्देश्य के जिसे उस आदेश में जगह मिलती है।(**एक्सप्रेस समाचार पत्र (पी)लिमिटेड**[35])। यही स्थिति तब होती है जब कोई आदेश किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, सिवाय उस उद्देश्य के जिसे उस आदेश में जगह मिलती है।दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जाने पर न्यायालय में विश्वास पैदा होना चाहिए और यह ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए।इस तरह के आरोपों को केवल लगाए जाने के आधार पर, या अनुमानों या अनुमानों से उत्पन्न विचारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। (**गोबर्धन लाल**[3]).हालाँकि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का

एक उचित अनुमान दलीलों और पूर्ववर्ती तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जा सकता है, लेकिन दलीलों और स्थापित तथ्यों की ठोस नींव होनी चाहिए, और इस तरह का निष्कर्ष आक्षेपों और अस्पष्ट सुझावों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है।(**राजेंद्र रॉय**[28])।न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन में, या इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में अस्पष्ट संकेत यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावना से प्रेरित है।

30. एक अनलंकृत कथन के अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दुर्भावनापूर्ण आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है।केवल "**दुर्भावनापूर्ण**" शब्द का उपयोग, अपने आप में, इस तरह की याचिका की स्वीकृति को उचित नहीं ठहराएगा।(**प्रबोध सागर**[36])।दुर्भावना के आरोप अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न उठाते हैं।इसलिए, इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए याचिका में पूरा विवरण देना आवश्यक है।यदि पर्याप्त अभिकथन और आवश्यक सामग्री अभिलेख में नहीं है, तो अदालत "**मछली पकड़ने**" या "**घूमने-फिरने**" की जांच नहीं करेगी।केवल दावा, अस्पष्ट कथन या अनलंकृत बयान कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।इसे तथ्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।इसके अलावा, दुर्भावनापूर्ण साबित करने का बोझ इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर है और बोझ "**बहुत भारी**" है।दुर्भावनापूर्ण आरोप बनाने की तुलना में अधिक आसानी से लगाया जाता है।यह एक हारे हुए मुकदमेबाज (**ई.पी. रोयप्पा**[37]; **गुलाम मुस्तफा**[38]; **अजीत कुमार नाग**[39] **और धामपुर शुगर (काशीपुर) लिमिटेड**[40]) की आखिरी शरणस्थली है।दुर्भावना के अस्पष्ट आरोप ऐसा करने वाले व्यक्ति पर पड़े बोझ को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, हालांकि इस संबंध में जो आवश्यक है वह पूरी तरह से सबूत नहीं है।प्राधिकार का दुरुपयोग उचित रूप से संभावित प्रतीत होना चाहिए। (**एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (पी) लिमिटेड**[35])।याचिका में विशेष रूप से और निश्चित रूप से आरोप लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्थापित करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय सबूत होने चाहिए। कानून के तहत अनुमान आदेश की प्रामाणिकता के पक्ष में है जब तक कि स्वीकार्य सामग्री द्वारा इसका खंडन न किया जाए।(**चन्द्र प्रकाश सिंह**[41] ; **निरोधि प्रकाश. गंगोली** [42]).

31. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को राज्य और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ लगाए गए द्वेष के आरोप को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए।दुर्भावना के आरोप को साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो राज्य और/या इसकी एजेंसियों और सहायकों की कार्रवाई को इस आधार पर अमान्य करने के लिए अदालत में जाता है कि यह दुर्भावना के कारण दूषित हो गया है।न्यायालय को अस्पष्ट और गंजे आरोपों या अनुचित दलीलों के आधार पर दुर्भावना या दुर्भावना के संदिग्ध निष्कर्ष निकालने के प्रलोभन का विरोध करना चाहिए।(**जसबीर सिंह छाबड़ा**[43]).

32. जहां कोई मामला लगभग पूरी तरह से दुर्भावना पर आधारित है, वहां द्वेष का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को आरोप के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, और यह दर्शाते हुए दुर्भावनापूर्ण दुश्मनी साबित करनी चाहिए कि प्रतिवादी या तो उसके खिलाफ द्वेष या दुर्भावना से प्रेरित था या अप्रत्यक्ष या अनुचित था। उद्देश्य, ऐसा न होने पर उत्तरदाताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपने उत्तर में इसके बारे में विस्तार से बताएं।प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, साथ ही उत्तरदाताओं की स्वीकारोक्ति और मामले की आसपास की परिस्थितियाँ, सद्भावना की कमी, या बुरे विश्वास को स्थापित करने के लिए स्वीकार्य हैं।(**केदार नाथ बहल**[44])। यह उस व्यक्ति के लिए है जो बुरे विश्वास का आरोप स्थापित करने के लिए किसी आदेश को अमान्य करना चाहता है।ऐसा आरोप

आसानी से या जिम्मेदारी की भावना के बिना लगाया जा सकता है, और यही कारण है कि अदालतों के लिए इसकी सावधानीपूर्वक और ध्यान से जांच करना आवश्यक है।(**एस. प्रताप सिंह** [45]**; केदार नाथ बहल** [44])।

33. आइए अब जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष स्थानांतरण के आदेश को पारित करने में प्रतिवादियों द्वारा बुरे विश्वास का मामला बनाने में सक्षम है।याचिकाकर्ता का यह तर्क कि स्थानांतरण का आदेश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "2013 अधिनियम") की खंड 12 (1) और (3) का उल्लंघन है, स्वीकृति के योग्य नहीं है। 2013 अधिनियम की धारा 12 किसी जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई से संबंधित है और उसकी उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जांच के लंबित रहने के दौरान, पीड़ित महिला, आंतरिक समिति या स्थानीय द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी। समिति, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता को (ए) पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की सिफारिश कर सकती है; या (बी) पीड़ित महिला को तीन महीने की अवधि तक छुट्टी देना; या (सी) पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करें जो निर्धारित की जा सकती है।धारा 12 (2) में कहा गया है कि इस धारा के तहत पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसकी वह अन्यथा हकदार होगी।धारा 12 (3) में कहा गया है कि, उप-धारा (1) के तहत, जैसा भी मामला हो, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोक्ता उप-धारा (1) के तहत की गई सिफारिशों को लागू करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।2013 अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) के संदर्भ में, संबंधित समिति को पीड़ित महिला (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता) को उसके लिखित अनुरोध पर स्थानांतरित करना आवश्यक है।माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, 2013 अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) का कोई अनुप्रयोग नहीं है।उक्त प्रावधान का प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित में किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से 2013 अधिनियम की धारा 12 (1) और (3) पर भरोसा करना गलत है।

34. याचिकाकर्ता का तर्क, कि उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए गए वचन पत्र की एक प्रति पेश करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यू.पी. में आदेश दिया गया। (ग) 6736/2016 दिनांक 12.04.2018 पारित होने के कारण स्थानांतरण समिति द्वारा स्थानांतरण आदेश को दूषित करने से पूर्व ही अस्वीकृत किया जाना अंकित है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.04.2018 के पत्र में उत्तरदाताओं की दलील दर्ज की, कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर रिट याचिका को वापस लेने के इच्छुक थे, और उसके बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं की मांगों के अधीन, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय 13.07.2016 के अपने फैसले के पैराग्राफ संख्या 35 में कैट द्वारा उल्लेखित किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना लिया जाएगा।

35. कैट द्वारा पैराग्राफ संख्या में नोट की गई असंगत परिस्थितियाँ। इसके दिनांक 13.07.2016 के आदेश के 35 थे कि स्थानांतरण का उद्देश्य याचिकाकर्ता को दंडित करना और हटाना था, जो उत्तरदाताओं के लिए असुविधाजनक हो गया था, और सार्वजनिक हित में नहीं था; याचिकाकर्ता, एक महिला, ने फर्जी पीएचडी से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए थे। संस्थान में प्रचलित डिग्रियाँ और बड़े पैमाने पर साहित्यिक चोरी; स्थानांतरण उनके

द्वारा उठाए गए मुद्दों के परिणामस्वरूप हुआ था; यह अधिकारियों का काम था कि वे आरोपों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त करें, और अपने घर को व्यवस्थित करें; स्थानांतरण से उसे असुविधा होगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हाल ही में एक बच्चे को गोद लिया है; यौन उत्पीड़न, फर्जी डिग्री और साहित्यिक चोरी जैसे मुद्दे उठाने पर याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता; और वह व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 के तहत सुरक्षा की हकदार एक व्हिसिल ब्लोअर थी।

36. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ज्ञानंत कुमार सिंह ने व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 के किसी भी प्रावधान पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया है, जिसका स्थानांतरण के आदेश के परिणामस्वरूप उल्लंघन किया गया है।दिनांक 14.05.2018 के स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि, कुल मिलाकर, विभिन्न ग्रेडों में 18 वैज्ञानिकों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया गया था।इन 18 में से, याचिकाकर्ता सहित एफ. आर. आई. देहरादून के 4 वैज्ञानिकों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।याचिकाकर्ता "ई" ग्रेड में एक वैज्ञानिक है।आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि, कुल मिलाकर, 7 वैज्ञानिक ग्रेड "ई" को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया था।स्थानांतरित किए गए 18 व्यक्तियों में से पाँच महिलाएँ हैं।इसलिए, हमारे लिए याचिकाकर्ता की याचिका को प्रतिग्रहण करना मुश्किल है कि स्थानांतरण आदेश सजा के उपाय के रूप में पारित किया गया था।जबकि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए फर्जी पीएचडी के गंभीर आरोप। संस्थान में डिग्रियों और साहित्यिक चोरी के मामले में निस्संदेह संस्थान द्वारा जांच की आवश्यकता होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे; और निस्संदेह, अपराधियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए (यदि ये आरोप सही हैं); इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की है, उसे बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, और उसे सेवा से सेवानिवृत्त होने तक उसी संस्थान में रखा जाना चाहिए।

37. याचिकाकर्ता पिछले लगभग 16 वर्षों से देहरादून स्थित संस्थान में काम कर रहा है, और प्रतिवादियों ने 18 कर्मचारियों, जिन्होंने एक विशेष स्टेशन पर 10 साल की सेवा पूरी कर ली थी, का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण कर दिया है।चूँकि उत्तरदाताओं को न्यायाधिकरण द्वारा पैराग्राफ संख्या में उल्लिखित की गई बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं थे। इसके निर्णय दिनांक 13.07.2016 के 35 में यह बात कम मायने रखती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति स्थानांतरण समिति के समक्ष नहीं रखी गई।न तो उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वचन पत्र, न ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) 6736/2016 दिनांक 12.04.2018 में पारित आदेश, उत्तरदाताओं को तबादलों के संबंध में अपनी सिफारिश से पहले स्थानांतरण समिति के समक्ष कैट, या दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति रखने के लिए बाध्य करता है।

38. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि श्री ए.एस. रावत और श्री रमन नौटियाल, जिनके खिलाफ उन्होंने और उनके पति ने आरोप लगाए थे, स्थानांतरण समिति का हिस्सा थे, यह केवल तभी होगा जब याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम हो कि ये दोनों व्यक्ति बुरे विश्वास में किए गए ऐसे स्थानांतरणों के लिए जिम्मेदार थे, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता और उनके पति ने उनके खिलाफ शिकायतें की थीं, स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप उचित होगा।यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन दोनों व्यक्तियों में से किसी को भी न्यायाधिकरण के समक्ष दायर ओए में या अब इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में

सूचीबद्ध नहीं किया गया है।जिस व्यक्ति पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, उसे कार्यवाही में प्रत्यर्थी पक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए, और उन आरोपों को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।उनकी अभाव में उन आरोपों की कोई जांच नहीं की जाएगी।अन्यथा, यह अपने आप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी निंदा करने के बराबर होगा।(**पी.पी. शर्मा**[46])।इसलिए, श्री ए.एस. की ओर से याचिकाकर्ता की दुर्भावनापूर्ण दलील की जांच करना हमारे लिए पूरी तरह से अनुचित होगा। रावत और श्री रमन नौटियाल, उनके पीठ पीछे।इसके अलावा स्थानांतरण का आदेश संस्थान के महानिदेशक द्वारा पारित किया गया था, और स्थानांतरण समिति में अन्य लोगों के साथ उपरोक्त दो व्यक्तियों ने केवल स्थानांतरण की सिफारिश की थी।इस संदर्भ में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जिस महानिदेशक ने विवादित स्थानांतरण आदेश पारित किया था, उसे भी प्रतिवादी ईओ-नामांकित के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

39. जैसा कि न्यायाधिकरण ने नोट किया है, इस रिट याचिका में दिए गए आदेश में, उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें स्थानांतरण के लिए पहचाना गया था, उन्हें दो अलग-अलग स्थानों के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने के लिए कहा गया था।ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने पोस्टिंग के लिए अपनी पसंद नहीं बताई और इसके बजाय, अधिकारियों से यह खुलासा करने के लिए कहा कि कौन से उम्मीदवार स्थानांतरण के लिए पात्र थे।उनकी शिकायत है कि कई अन्य लोग भी हैं जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है, और उन्हें भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, वर्तमान कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती क्योंकि उन व्यक्तियों में से कोई भी, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का आरोप है कि वे भी स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें इस रिट याचिका में प्रतिवादी ईओ-नामांकित के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।किसी भी घटना में, केवल यह संभावना कि कुछ अन्य, जिन्हें भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, याचिकाकर्ता के इस दावे को उचित नहीं ठहराएगा कि उसे देहरादून में ही बनाए रखा जाना चाहिए।जैसा कि **चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य**[47] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था:

> "..... सामान्यतया, केवल यह तथ्य कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरण ने समान स्थिति वाले किसी अन्य व्यक्ति के मामले में एक विशेष आदेश पारित किया है, कभी भी भेदभाव की दलील पर याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट जारी करने का आधार नहीं हो सकता है .दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश कानूनी और वैध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।याचिकाकर्ता के मामले में इसका पालन करने का निर्देश देने से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए।यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया आदेश कानून के विपरीत पाया जाता है या उसके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित नहीं पाया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे अवैध या अनुचित आदेश को प्रतिवादी को बाध्य करने वाली रिट जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है- अवैधता को दोहराने या कोई अन्य अनुचित आदेश पारित करने का अधिकार।उच्च न्यायालय की असाधारण और विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।मात्र इसलिए कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरण ने एक अवैध/अनुचित आदेश पारित किया है, यह उच्च न्यायालय को प्राधिकरण को बार-बार उस अवैधता को दोहराने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देता है।अवैध/अनुचित कार्रवाई को सुधारा जाना चाहिए, यदि यह कानून के अनुसार किया जा सकता है - वास्तव में, जहां भी संभव हो, अदालत को ऐसे गलत आदेशों को कानून के अनुसार सही करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश देना चाहिए - लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो भी यह देखना मुश्किल है कि इसे इसकी पुनरावृत्ति का आधार कैसे बनाया जा सकता है। प्रतिवादी

प्राधिकारी को अवैधता को दोहराने का निर्देश देने से इनकार करके, अदालत पहले के अवैध कार्य/आदेश को नज़रअंदाज नहीं कर रही है और न ही ऐसा अवैध आदेश भेदभाव की वैध शिकायत का आधार बन सकता है।ऐसी दलीलों को अमल में लाना कानून के हितों के प्रति प्रतिकूल होगा और सार्वजनिक हित के लिए अपूरणीय क्षति होगी।यह कानून और कानून के शासन की अवहेलना होगी।निःसंदेह, यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश एक वैध और न्यायोचित पाया जाता है तो इसका पालन किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को भी इसी तरह की राहत दी जा सकती है यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला अन्य व्यक्तियों के मामले के समान है। लेकिन फिर अदालत में मौजूद याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने और राहत मांगने के बजाय उसकी अभाव में किसी अन्य व्यक्ति के मामले की जांच क्यों की जाए।क्या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई की शुद्धता की जांच करने की तुलना में याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगी गई राहत के लिए अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की पात्रता की जांच करना अधिक उचित और सुविधाजनक नहीं है, जो अन्य है व्यक्ति न तो मामले से पहले है और न ही उसका मामला है।हमारी सुविचारित मत में, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इस तरह का मार्ग न तो उचित होगा और न ही वांछनीय।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाले कानून और अच्छी तरह से स्वीकृत मानदंडों की अनदेखी नहीं कर सकता है और कह सकता है कि क्योंकि एक मामले में एक विशेष आदेश पारित किया गया है या एक विशेष कार्रवाई की गई है, इस तथ्य की परवाह किए बिना उसे दोहराया जाना चाहिए कि ऐसा आदेश या कार्रवाई कानून के विपरीत है या अन्यथा।प्रत्येक मामले का निर्णय प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, उसके अपने गुण-दोष, तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

40. भले ही कुछ अन्य लोगों को बनाए रखना अवैध माना जाए, याचिकाकर्ता केवल यह दावा कर सकती थी कि उन्हें भी अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, न कि उसे देहरादून में बनाए रखा जाना चाहिए।

41. यह तर्क कि कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया गया था, आधा स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने के एक घंटे बाद, और इससे उसकी मंशा का पता चला अधिकारियों द्वारा उसे आसानी से बाहर निकालना भी स्वीकार्यता के लायक नहीं है। यदि नियम विरुद्ध कार्यमुक्ति आदेश जारी किया गया तो यह होगा कार्यमुक्ति आदेश, न कि स्थानांतरण आदेश, जो निष्प्रभावी माना जाएगा। इसके तुरंत बाद ऐसा कार्यमुक्त आदेश जारी करने का जो भी औचित्य हो स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश 14.05.2018 को पारित किया गया था, तथ्य यह है कि दिनांक 14.05.2018 को स्थानांतरण आदेश पारित होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल से अंतरिम संरक्षण प्राप्त कर लिया है आज तक देहरादून में कार्यरत हूँ।

42. दिनांक 14.08.2015 को संस्थान के पूर्व सचिव श्री वी. खांडेकर द्वारा हस्ताक्षरित नोट पर भरोसा करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ।हालांकि उक्त नोट में यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता के देहरादून में बने रहने से निश्चित रूप से माहौल खराब होगा, वह दूसरों को फंसाने के प्रयासों में शामिल हो सकती है, और उसे देहरादून से दूर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, उपरोक्त नोट पर श्री वी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। खांडेकर द्वारा दिनांक 14.05.2018 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश की तिथि से लगभग तीन वर्ष पूर्व दिनांक 14.08.2015 को।उक्त समर्थन ओ. ए. सं. में न्यायाधिकरण के पहले के आदेश से पहले भी किया गया था। 2015

का 4081 दिनांक 13.07.2016।चूंकि स्थानांतरण का विवादित आदेश प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में स्थानांतरण करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति मांगने के बाद पारित किया गया था, इसलिए घटनाओं पर निर्भरता बढ़ गई, जो डब्ल्यू.पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से लगभग तीन साल पहले हुई थी। (सी) क्रमांक 6736 ऑफ़ 2016 दिनांक 12.04.2018 ग़लत है।

43. **श्रीमती में. नागरत्नम्मा और अन्य**[8], जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से भरोसा किया गया है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि एक सरकारी कर्मचारी को एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरण पर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि प्रत्यर्थी इस तरह का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिससे याचिकाकर्ता जोधपुर में अपने स्थानांतरित स्टेशन पर शामिल हो पाएगी।

44. "प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं" और "प्रशासनिक कारणों" के बीच जो सूक्ष्म अंतर करने की मांग की गई है, वह भी स्वीकार्यता के योग्य नहीं है।"अनिवार्यता" शब्द का अर्थ तत्काल आवश्यकता है, और "प्रशासनिक अत्यावश्यकता" पर स्थानांतरण का अर्थ प्रशासनिक आधार पर किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता होगी।केवल यह तथ्य कि स्थानांतरण के आदेश में यह दर्ज है कि स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, और यह नहीं बताता है कि स्थानांतरण प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर किया जा रहा था, बहुत कम मायने रखता है।यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सिर्फ शब्दों का खेल है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।

45. जबकि याचिकाकर्ता शिकायत करती है कि न्यायाधिकरण के दिनांक 13.07.2016 के पूर्व आदेश के बावजूद उसे कोई काम नहीं दिया गया था, प्रत्यर्थी का तर्क है कि उसे कोई काम नहीं दिया जाना था।

46. ऐसा कोई नियम भी हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसमें स्थानांतरण आदेश पारित होने से पहले किसी कर्मचारी को नोटिस पर रखने की आवश्यकता हो।न्यायाधिकरण ने मामले की बहुत विस्तार से जांच की है, और यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस तरीके से एक संगठन को चलाया जाना चाहिए, वह उन लोगों के लिए है, जो इसके मामलों के शीर्ष पर हैं, और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में ऐसे मामलों में विशेषज्ञता की कमी है।न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ऐसा दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है जिसे बिल्कुल नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि केवल तभी यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, हस्तक्षेप करने के लिए अपने उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में उचित होगा।

47. किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उत्प्रेषण-लेख याचिका में आक्षेपित न्यायाधिकरण का आदेश, हमारी प्रत्ययी क्षेत्राधिकार के स्पष्ट वारंट अभ्यास में त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।कोई लागत नहीं।

(एन.एस. धनिक, न्या.)	**(रमेश रंगनाथन, मु. न्या.)**
19.03.2019	19.03.2019

राहुल